नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 214
दि. 08.05.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

CBI के नए निदेशक पर मंथन तेज, अगले सप्ताह हो सकता है बड़ा फैसला; देश की शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों में व्यापक फेरबदल के संकेत

नई दिल्ली। देश की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के नए निदेशक की नियुक्ति को लेकर राजधानी दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। मौजूदा निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 25 मई को समाप्त होने जा रहा है और इसके साथ ही केंद्र सरकार तथा उच्च स्तरीय चयन समिति के बीच नए चेहरे को लेकर गंभीर मंथन शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है, जिसमें नए सीबीआई निदेशक के नाम पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इस नियुक्ति को केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि देश की जांच और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की दिशा तय करने वाले बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, इस बार सीबीआई निदेशक पद की दौड़ में करीब आधा दर्जन वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं। इनमें केंद्रीय एजेंसियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और विभिन्न राज्यों के पुलिस संगठनों में लंबे अनुभव वाले अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार इस बार ऐसे अधिकारी के चयन पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसे बड़े स्तर की जांच, आतंकवाद विरोधी अभियानों, संगठित अपराध और संवेदनशील मामलों के संचालन का व्यापक अनुभव हो।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, नए निदेशक के चयन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक अगले सप्ताह प्रस्तावित है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। यही समिति सीबीआई निदेशक के नाम को अंतिम मंजूरी देती है। माना जा रहा है कि बैठक में वरिष्ठता, अनुभव, प्रशासनिक रिकॉर्ड, केंद्रीय एजेंसियों में कार्य और संवेदनशील मामलों को संभालने की क्षमता जैसे कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद को मई 2023 में दो वर्ष के लिए सीबीआई

निदेशक नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार भी दिया गया। हालांकि अब मौजूदा नियमों के तहत अधिकतम सेवा विस्तार की सीमा को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार नए चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार एजेंसी में नए नेतृत्व के जरिए आने वाले वर्षों की जांच रणनीति को और मजबूत करना चाहती है।

इस बीच जिन अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं, उनमें केंद्रीय सुरक्षा बलों और केंद्रीय एजेंसियों में कार्यरत कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, एक वरिष्ठ अधिकारी जो वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के प्रमुख पद पर कार्यरत हैं, उन्हें प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा है। नक्सल विरोधी अभियानों, आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उनकी भूमिका को लेकर सरकार के भीतर सकारात्मक राय बताई जा रही है। इसके अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी उन्हें मजबूत समर्थन मिलने की चर्चा है।

इसके साथ ही कुछ ऐसे अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्होंने पूर्व में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), खुफिया इकाइयों और राज्य पुलिस संगठनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। इनमें ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें बड़े आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों, हाई-प्रोफाइल जांच और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने का अनुभव रहा है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार इस बार ऐसे अधिकारी को प्राथमिकता दे सकती है, जो तकनीकी जांच, साइबर अपराध और अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क से जुड़े मामलों को भी प्रभावी ढंग से संभाल सके।

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के साथ-साथ देश की अन्य प्रमुख सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों में भी बड़े स्तर पर बदलाव की संभावना जताई जा रही है। खुफिया ब्यूरो (IB) के वर्तमान प्रमुख का कार्यकाल भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्हें पिछले वर्ष सेवा विस्तार दिया गया था और अब यह संभावना जताई जा रही है कि सीमावर्ती सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें एक और विस्तार दिया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भी आने वाले समय में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की संभावना बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, यदि सीआरपीएफ प्रमुख को किसी नई जिम्मेदारी में स्थानांतरित किया जाता है, तो वरिष्ठ स्तर के अन्य अधिकारियों को पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और अन्य केंद्रीय बलों में भी नेतृत्व स्तर पर बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह समय देश की जांच और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सीबीआई जैसे संस्थान के नेतृत्व का प्रभाव केवल एजेंसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर पूरे देश की कानून व्यवस्था और जांच प्रणाली पर पड़ता है। यही कारण है कि सरकार इस नियुक्ति को बेहद संवेदनशील और रणनीतिक दृष्टि से देख रही है।

राजनीतिक हलकों में भी इस नियुक्ति को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। विपक्ष की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि चयन प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और संतुलित रहती है, जबकि सरकार इस पद के लिए अनुभवी और सक्षम अधिकारी के चयन को प्राथमिकता देने की बात कह रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शीर्ष स्तर पर कई दौर की चर्चाओं और विचार-विमर्श के बाद अंतिम नाम पर सहमति बनाई जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार आने वाले वर्षों में केंद्रीय जांच एजेंसियों को और अधिक तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। डिजिटल फॉरेंसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जांच, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय और हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराधों की निगरानी को लेकर नई रणनीति तैयार की जा रही है। ऐसे में नए सीबीआई निदेशक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

फिलहाल देश की राजनीतिक, प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हलकों की नजर अगले सप्ताह होने वाली संभावित बैठक पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद केवल सीबीआई ही नहीं, बल्कि देश की कई प्रमुख सुरक्षा और जांच एजेंसियों के नेतृत्व को लेकर भी तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है।

दिल्ली फ्लाइट में महुआ मोइत्रा का आरोप, विमान में बदसलूकी और वीडियो बनाने का दावा; एयरलाइन से सख्त कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस की तेजतर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने एक निजी विमान सेवा की दिल्ली जा रही उड़ान में अपने साथ कथित बदसलूकी और उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाकर राजनीतिक और विमानन क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है। सांसद ने इस पूरी घटना को केवल असहज व्यवहार नहीं बल्कि व्यक्तिगत सुरक्षा और गरिमा का सीधा उल्लंघन बताते हुए एयरलाइन कंपनी और केंद्र सरकार से तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

महुआ मोइत्रा ने अपने बयान में बताया कि वह संसद की रक्षा मामलों से जुड़ी स्थायी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रही थीं। उनके अनुसार उन्होंने विमान में पहली पंक्ति की निर्धारित सीट पर यात्रा शुरू की थी। उड़ान के दौरान कुछ यात्री बाद में विमान में सवार हुए, जिनके व्यवहार ने उन्हें असहज महसूस कराया। सांसद का आरोप है कि इन यात्रियों का एक समूह, जिसमें चार से छह लोग शामिल थे, लगातार उनकी ओर घूरता रहा और विमान के भीतर असामान्य व्यवहार करता रहा।

उनके अनुसार, कुछ समय बाद वे यात्री विमान के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए, लेकिन उनका व्यवहार सामान्य नहीं रहा और वे लगातार संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त दिखाई दिए। महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि पूरी यात्रा के दौरान उनका ध्यान उन लोगों के व्यवहार

पर केंद्रित रहा, जिससे उन्हें मानसिक रूप से असहज स्थिति का सामना करना पड़ा।

सबसे गंभीर आरोप उन्होंने यह लगाया कि विमान के दिल्ली पहुंचने और दरवाजा खुलने से ठीक पहले उन लोगों ने उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया और उनका वीडियो बनाने का प्रयास किया। सांसद ने इसे केवल असभ्य व्यवहार नहीं बल्कि एक संगठित और जानबूझकर की गई हरकत बताया, जिससे उनकी निजी सुरक्षा और गरिमा प्रभावित हुई।

महुआ मोइत्रा ने कहा कि विमान जैसे सीमित और नियंत्रित वातावरण में इस तरह की घटना यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने यह भी कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद यदि उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, तो आम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है।

उन्होंने विमान सेवा कंपनी से मांग की है कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की जाए। उनके अनुसार, फ्लाइट के चालक दल की रिपोर्ट, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और यात्रियों की सूची की गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि जिन यात्रियों पर आरोप लगे हैं, उनकी पहचान कर उन्हें भविष्य में हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किया जाए।

सांसद ने केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से भी इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। उनका कहना है कि विमानन क्षेत्र में यात्रियों की सुरक्षा और गरिमा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

इस घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताते हुए जांच की मांग की है, जबकि कुछ नेताओं का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए। वहीं विमान सेवा कंपनी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे मामला और अधिक चर्चा में आ गया है। विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका केबिन क्रू की रिपोर्ट और फ्लाइट रिकॉर्डिंग की होती है, जो वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर सकती है।

यह घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब देश में विमान यात्रा में सुरक्षा और यात्री अनुशासन को लेकर पहले से ही कई चर्चाएं चल रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव की आवश्यकता को भी उजागर कर सकता है।

फिलहाल इस पूरे मामले की जांच और एयरलाइन की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह मामला वास्तव में सुरक्षा चूक था, यात्री विवाद था या फिर किसी अन्य परिस्थितियों का परिणाम।

अनिल अंबानी का एनडीटीवी पर मानहानि मुकदमा, गलत रिपोर्टिंग का आरोप; दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। उद्योगपति अनिल अंबानी ने मीडिया समूह एनडीटीवी और उससे जुड़े वरिष्ठ संपादकीय अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह मामला उनके कारोबारी समूह से जुड़ी जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों की कथित गलत और भ्रामक रिपोर्टिंग को लेकर सामने आया है। याचिका में अनिल अंबानी ने दावा किया है कि मीडिया संस्थान द्वारा प्रकाशित और प्रसारित सामग्री ने उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है।

अनिल अंबानी द्वारा दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि एनडीटीवी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़ी कार्रवाईयों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया, जिससे दर्शकों और आम जनता के बीच उनके खिलाफ नकारात्मक धारणा बनी। याचिका में यह भी कहा गया है कि रिपोर्टिंग में तथ्यों की बजाय पूर्वाग्रह और एकतरफा दृष्टिकोण अधिक दिखाई देता है, जिससे उनके कारोबारी समूह की साख प्रभावित हुई है।

मुकदमे में अनिल अंबानी ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि संबंधित

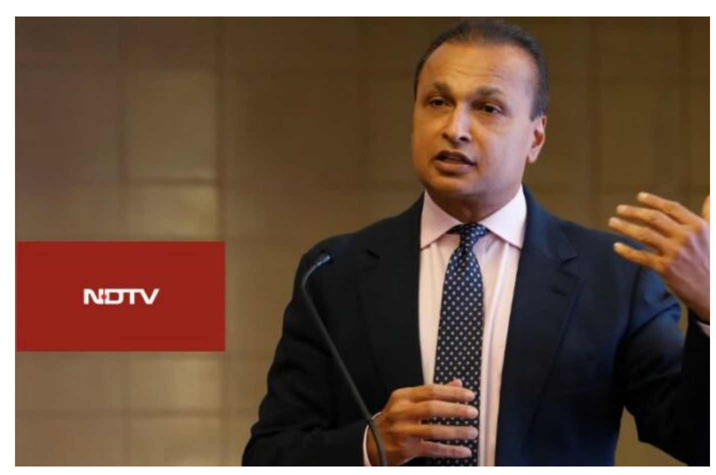

मीडिया समूह के कुछ लोग उनकी कंपनियों पर नियंत्रण या कब्जे की कोशिश कर रहे हैं और इसी उद्देश्य से लगातार नकारात्मक खबरों का प्रसार किया जा रहा है। उनके अनुसार, पिछले कुछ महीनों में उनके खिलाफ कई तीखे और आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित किए गए, जिनका उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना था।

याचिका में अनिल अंबानी ने दो करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि यदि उन्हें यह राशि प्रदान की जाती है, तो वह इसे किसी सामाजिक या जनहित कार्य के लिए दान कर देंगे। इस पहलू ने मामले को और अधिक चर्चा में ला दिया है, क्योंकि यह केवल कानूनी विवाद नहीं बल्कि सार्वजनिक प्रतिष्ठा और मीडिया जिम्मेदारी से जुड़ा मामला बन गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एनडीटीवी से जुड़े प्रमुख अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। जिन लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है उनमें समाचार चैनल के प्रधान संपादक राहुल कनवाल, प्रबंध संपादक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अदालत ने सभी पक्षों को आगामी सुनवाई में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 जुलाई निर्धारित की है, जब दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी। अदालत यह भी तय करेगी कि क्या इस मामले में अंतरिम राहत की आवश्यकता है या नहीं।

इस घटनाक्रम के बाद मीडिया और कॉरपोरेट जगत में भी चर्चा तेज हो गई है। मीडिया विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला एक बार फिर प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदार पत्रकारिता के बीच संतुलन पर बहस को जन्म दे सकता है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मानहानि मामलों में अदालतें तथ्यों, रिपोर्टिंग के स्रोत और मंशा की गहन जांच करती हैं।

फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस मामले ने कॉरपोरेट और मीडिया संबंधों को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में अदालत की कार्यवाही इस विवाद की दिशा तय करेगी।

केरल में सत्ता वापसी के बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान, तीन दिग्गज नेताओं के बीच बढ़ी खींचतान

तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जहां संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की सत्ता में वापसी ने कांग्रेस खेमे में उत्साह भर दिया है, वहीं अब मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के भीतर अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और यूडीएफ को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है, लेकिन सरकार गठन से पहले ही शीर्ष पद को लेकर मचे सियासी संघर्ष ने नेतृत्व के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। इस चुनाव में कांग्रेस ने 63 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि उसकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के साथ मिलकर संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने कुल 102 सीटें हासिल की हैं। इस मजबूत जनादेश के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के भीतर सहमति नहीं बन पा रही है।

मुख्यमंत्री पद की दौड़ में इस समय तीन प्रमुख नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इनमें विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल तथा अनुभवी नेता रमेश चेन्निथला शामिल हैं। तीनों ही नेताओं का अपना-अपना मजबूत राजनीतिक आधार है और समर्थकों के बीच उनका प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व इस मुद्दे पर संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी भी गुट में असंतोष न बढ़े। हालांकि जमीनी स्तर पर स्थिति अलग दिखाई दे रही है, जहां समर्थक खुलकर अपने-अपने नेताओं के पक्ष में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं।

इस बीच अलाप्पुझा जिले में के. सी. वेणुगोपाल के खिलाफ कुछ पोस्टर लगाए जाने से राजनीतिक माहौल और गरमा गया है। इन पोस्टरों में उपचुनाव की संभावित स्थिति का जिक्र करते हुए उन्हें ऐसे किसी कदम से बचने की सलाह दी गई है, जिससे पार्टी के भीतर अस्थिरता पैदा हो। हालांकि दूसरी ओर वेणुगोपाल के समर्थकों ने भी पोस्टर लगाकर उन्हें निर्णायक और मजबूत नेतृत्व क्षमता वाला नेता बताया है।

इसी तरह वी. डी. सतीशन के समर्थकों ने नेट्टूर में प्रदर्शन कर उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठाई है। चुनाव प्रचार के दौरान सतीशन को यूडीएफ का प्रमुख चेहरा माना गया था और उनकी रणनीति को पार्टी की जीत का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। उनके समर्थकों का कहना है कि जमीनी स्तर पर नेतृत्व करने और जनता से सीधा जुड़ाव रखने की वजह से वह मुख्यमंत्री पद के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं।

रमेश चेन्निथला का नाम भी इस दौड़ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे लंबे समय से पार्टी संगठन और विधानसभा राजनीति में सक्रिय रहे हैं और उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है। पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर उन्हें मौका दिया जाना चाहिए।

हालांकि कांग्रेस हाईकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किसी एक नाम पर सहमति बनाने के बावजूद दूसरे गुटों में असंतोष न पैदा हो। केरल कांग्रेस का इतिहास गुटीय राजनीति से जुड़ा रहा है, ऐसे में यह निर्णय पार्टी की भविष्य की एकता और स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति कांग्रेस के लिए "जीत के बाद की सबसे बड़ी परीक्षा" है। चुनावी सफलता के बावजूद यदि नेतृत्व चयन पर सहमति नहीं बनती, तो इसका असर आने वाले शासन पर भी पड़ सकता है। फिलहाल पार्टी के भीतर लगातार बैठकों और अनौपचारिक चर्चाओं का दौर जारी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस हाईकमान इस पर अंतिम निर्णय ले सकता है। तब तक केरल की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर यह खींचतान और तेज होने की संभावना है।

संपादकीय

आतंक की घटनाओं पर राजनीति अस्वीकार्य

गाहे-बगाहे पंजाब में शांति भंग करने के अनेक कुत्सित प्रयास होते नजर आए हैं। सीमा पार से पंजाब का सुख-चैन छीनने के षड्यंत्र काले दौर से लेकर अब तक रुके नहीं हैं। नशे और बेरोजगारी को हथियार बनाकर भटके युवाओं को इन साजिशों का हथियार बनाने के मामले भी उजागर हुए हैं। पंजाब में हाल ही में दो धमाके हुए, पहला जालंधर में बीएसएफ चौकी के बाहर और दूसरा अमृतसर में सेना की छावनी के पास हुआ। सेना और सुरक्षा बलों को लक्षित इन हमलों के घातक मंसूबों को समझा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर समय और लक्ष्य के लिहाज से इतने करीबी हमलों के निहितार्थ समझना कठिन नहीं है कि ये महज सामान्य मामले नहीं थे। अब भले ही इन धमाकों की तीव्रता कम रही हो,लेकिन इनमें गंभीर रणनीतिक चेतावनी छिपी है। वह ये कि भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों की हिफाजत को आंका जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव द्वारा सैन्य क्षेत्र के पास हुए धमाकों में विस्फोटक उपकरण यानी आईडीपी के इस्तेमाल की पुष्टि करना, खतरे की गंभीरता को रेखांकित करता है। निस्संदेह, ये महज आकस्मिक घटनाएं मात्र नहीं हैं। ये सुनियोजित तरीके व जासूसी के जरिये रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास की कमजोर कड़ियों को तलाशने की कुत्सित कोशिश है। अब चाहे इन आतंकी गतिविधियों के तार स्थानीय साजिश से जुड़े हों या फिर सीमा पार से साजिश को अंजाम दिया गया हो, कह सकते हैं कि मिलाजुला षड्यंत्र हो, मगर तौर-तरीका स्पष्ट है। हालांकि, राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक लाइन के अनुरूप बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसका दोष भाजपा पर मढ़ा है। वहीं भाजपा आप सरकार पर आरोप लगा रही है कि वह राज्य को सुरक्षा देने में विफल रही है। बहरहाल, भले ही आरोप-प्रत्यारोप का यह खेल नेताओं को राजनीतिक लाभ-हानि के गणित के अनुरूप लगता हो, मगर राज्य की सुरक्षा के नजरिये से अदूरदर्शी कदम ही कहा जाएगा।

यह विडंबना ही है कि पंजाब के राजनेता अतीत के स्याह दौर की घातकता से कोई सबक नहीं सीखते हैं। राजनेताओं की संकीर्णता और दूरगामी प्रभावों को नजरअंदाज करके की गई बयानबाजी ही चिंगारी को आग बनाने का काम करती है। जिसकी कीमत दशकों तक पंजाब के लोगों व राज्य की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है। यह सामान्य तथ्य है कि कि जब भी इस संवेदनशील व सीमावर्ती राज्य पर कोई सुरक्षा संकट पैदा हो, उसके लिये राजनीतिक भेदभाव भुलाकर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। टकराव की राजनीति से राज्य का अहित ही होगा। निस्संदेह, पंजाब का अतीत इस मामूली अशांति के प्रति भी विशेष रूप से संवेदनशील होने की जरूरत बताता है। दशकों तक पंजाब ने सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था और खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों हेतु देशव्यापी ख्याति अर्जित की है। लेकिन हाल की घटनाओं ने हमारी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया ही है। यह गंभीर मसला है कि इस सीमावर्ती संवेदनशील राज्य में दस दिनों के भीतर तीन सुनियोजित व उच्च तकनीक से लैस विस्फोट हुए हैं। ये धमाके सभी पक्षों की मेहनत से अर्जित साख को धूमिल करने के जोखिम को बढ़ाते हैं। सवाल मात्र यही नहीं है कि इन धमाकों के लिये कौन जिम्मेदार है। प्रश्न यह भी है कि क्या इन धमाकों के बाबत खुफिया सूचनाओं को नजरअंदाज किया गया है? या फिर मिली हुई खुफिया सूचनाओं के आधार पर समन्वित प्रतिक्रिया देने में कहीं चूक हुई है? वास्तव में वक्त की सबसे बड़ी जरूरत इस बात को लेकर है कि हम ऐसी किसी भी चुनौती को लेकर एक समन्वित प्रतिक्रिया दें। केंद्र व राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी का बेहतर ढंग से आदान-प्रदान किया जाए। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा घेरे के दायरे का तत्काल प्रभाव से सुरक्षा ऑडिट किया जाए। इन साजिशों पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। खासकर लगातार गहरी होती ड्रोन आधारित घुसपैठ के खतरों को रोकने के लिये युद्धस्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है। ड्रोन आज अवैध हथियारों व नशीले पदार्थों की तस्करी का साधन बन रहे हैं। जनता का मनोबल बढ़ाना जरूरी है, लेकिन सुरक्षा जोखिमों को कम न आंका जाए।

'सरहदी राज्य' के नारे संग चुनावी रणनीति

> “ पश्चिम बंगाल और असम जैसे 'बॉर्डर स्टेट्स' के बाद अब भाजपा पंजाब के लिए 'सरहदी राज्य का नारा' देने की तैयारी में है। भाजपा मुख्यालय में बंगाल-असम जीत के जश्न के दौरान भी इसकी झलक मिली।

बंगाल जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पैनी नजर अब पंजाब पर है। अकाली दल के साथ पहले भी पंजाब में सत्ता का स्वाद चख चुकी भाजपा अब यहां 'एकला चलो' की रणनीति पर काम कर रही है। बेशक पंजाब के सियासी शतरंज में शह-मात के खेल में गोटी फिट करना टेढ़ी खीर है, लेकिन पश्चिम बंगाल और असम जैसे 'बॉर्डर स्टेट्स' के बाद अब वह पंजाब के लिए 'सरहदी राज्य का नारा' देने की तैयारी में है। भाजपा मुख्यालय में बंगाल-असम जीत के जश्न के दौरान भी इसकी झलक मिली। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ इस जश्न में अनेक सिख नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान इन लोगों ने खूब नारे लगाए।

पंजाब को लेकर भाजपा इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि उसे यकीन है कि फिर से एकजुट हो रहे 'इंडिया' गठबंधन की एकता यहां नहीं रहेगी। इस राज्य में कांग्रेस तो अकेले लड़ेगी ही, आम आदमी पार्टी (आप) सत्ता में वापसी की अलग से पूरी कोशिश करेगी। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि भाजपा के विजय रथ को पंजाब रोकेगा। अकाली दल अपनी तैयारी कर ही रहा है। कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों की भी चुनाव में भूमिका होती है। ऐसे में भाजपा बिखरे विपक्ष का फायदा उठाएगी। इसी तरह का लाभ उसे बंगाल और असम में भी मिला है।

चुनाव परिणाम के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये आखिरी विजय है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि पंजाब के बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। आप से भाजपा में गए राज्यसभा सदस्यों का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने पंजाबियों की इन सीटों को लूटा है। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पहली प्रतिक्रिया में आरोप लगाया कि भाजपा ने सौ सीटों की लूट की है। इसी तरह सपा प्रमुख अखिलेश यादव एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव में सीट चोरी का आरोप लगाया है। वह मोदी के खिलाफ अक्सर ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं।

इस बीच, भाजपा नेताओं ने 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में मिली सफलता को दोहराने की उम्मीद जताई है। भाजपा के रणनीतिकार सरहदी राज्य की सुरक्षा, नशा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। वैसे पंजाब के अलावा अगले साल गुजरात, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हैं, लेकिन भाजपा के लिए पंजाब प्रमुख है। पार्टी यहां अपना वर्चस्व बनाकर एक संदेश देने की कोशिश में है।

अन्य राज्यों में भी भाजपा की तैयारी जोरों पर है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। इन राज्यों में पार्टी पदाधिकारियों की विभिन्न बैठकों में भाग ले चुके नबीन अब पीएम और गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा कर रहे हैं। इन राज्यों के साथ ही भाजपा उत्तराखंड के लिए भी जोरशोर से जुट गयी है। उत्तराखंड, गुजरात भी एक तरह से सरहदी राज्य हैं। उत्तराखंड में जहां चीन और नेपाल की सीमाएं लगती हैं, वहीं गुजरात का एक हिस्सा पाकिस्तान सीमा से सटा है। पंजाब भी पाकिस्तान सीमा से सटा है। मणिपुर राज्य भी म्यांमार से सटा है और यहां कुछ समय तक अशांति रही। हालांकि अभी भी इस सरहदी राज्य में हिंसा की छिटपुट वारदातें हो रही हैं। दो समुदायों के बीच संघर्ष को सुलझाने का काम भाजपा सरकार नहीं कर पाई है। मणिपुर को लेकर कांग्रेस अनेक बार भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधती रही है।

काबिल-ए-गौर है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा की सरकार है, जबकि पंजाब में आप और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 207 सीटें जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया। यहां उसने तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया। असम में सत्तारूढ़ राजग दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के बाद लगातार तीसरी बार राज्य में सत्ता में लौटा है। राजग ने 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा ने 82 सीट पर जीत हासिल की जबकि उसके सहयोगी दलों- बोडो पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) और असम गण परिषद (एजीपी) को 10-10 सीट पर जीत मिली है। राज्य में भाजपा ने पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया है।

भारत के ज्यादातर राज्यों में काबिज हो चुकी भाजपा या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) अब पूरा जोर पंजाब पर लगाएगी। उधर, हालिया हार के बाद इंडिया गठबंधन एकजुट होने की एक बार फिर कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि पंजाब में भाजपा अपने पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के साथ फिर से मैदान में उतरने की कोशिश करती है या फिर इस राज्य में भी वह कोई नया प्रयोग करेगी। वैसे दोनों दलों के कुछ स्थानीय कार्यकर्ता इस गठबंधन को जरूरी बता रहे हैं, लेकिन शीर्ष स्तर पर इस तरह की किसी चर्चा की कोई बात सामने नहीं आई है। इस एका की बात के उलट भाजपा के बड़े नेता सार्वजनिक मंचों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। लगभग आठ महीने बाद चुनावी रण में पार्टियां नजर आएंगी।

प्रेरणा

जब चुप हो गई चिड़ियों की आवाज़

अवंतिका नगर अपनी हरियाली, उपजाऊ खेतों और समृद्ध किसानों के लिए प्रसिद्ध था। वहां की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि हर मौसम में खेत सोने की तरह चमकते थे। किसान पूरे मन से मेहनत करते, समय पर बीज बोते और अच्छी फसल की उम्मीद में दिन-रात खेतों में पसीना बहाते थे। लेकिन कई वर्षों से नगर के लोगों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। जैसे ही फसल पकने लगती, सैकड़ों पक्षी खेतों में उतर आते और दाने चुगने लगते। किसानों को लगता कि उनकी मेहनत धीरे-धीरे खत्म हो रही है। वे दिनभर खेतों में डंडे लेकर पहरा देते, आवाजें निकालकर पक्षियों को उड़ाते, लेकिन कुछ ही देर बाद पक्षी फिर लौट आते। यह क्रम लगातार चलता रहा और किसानों के मन में पक्षियों के प्रति गुस्सा भरता गया। धीरे-धीरे यह असंतोष पूरे नगर में फैल गया। लोगों को लगने लगा कि यदि पक्षियों को नहीं रोका गया, तो एक दिन वे पूरी फसल खत्म कर देंगे। नगर के व्यापारी और किसान एकत्र होकर राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने दुखी स्वर में कहा कि उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल पा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण पक्षी हैं। किसानों ने राजा से मांग की कि इन पक्षियों से छुटकारा दिलाया जाए। राजा ने किसानों की व्यथा सुनी, लेकिन उसने समस्या को गहराई से समझने की कोशिश नहीं की। क्रोध और जल्दबाजी में उसने आदेश दे दिया कि नगर के सभी पक्षियों को मार दिया जाए, ताकि खेत पूरी तरह सुरक्षित हो सकें।

राजा का आदेश मिलते ही सैनिक सक्रिय हो गए। उन्होंने पूरे नगर और आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों को मारना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में पेड़ों की डालियां सूनी हो गईं। सुबह की मधुर चहचहाहट समाप्त हो गई। आसमान में उड़ते झुंड दिखाई देना बंद हो गए। शुरुआत में लोगों को लगा कि अब उनकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है। किसानों ने राहत की सांस ली और नए मौसम की तैयारी शुरू कर दी। इस बार उन्होंने बिना किसी डर और चिंता के बीज बोए। उन्हें विश्वास था कि अब उनकी फसल सुरक्षित रहेगी और पहले से कहीं अधिक उत्पादन होगा।

समय बीतता गया। खेतों में छोटे-छोटे पौधे निकलने लगे। बारिश भी अच्छी हुई और मौसम भी अनुकूल था। किसानों को लगने लगा कि इस बार उन्हें भरपूर फसल मिलेगी। लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद खेतों की स्थिति बदलने लगी। कई जगह पौधे अचानक सूखने लगे। कुछ खेतों में बीज अंकुरित ही नहीं हुए। किसानों ने सोचा कि शायद मिट्टी में कमी है या पानी पर्याप्त नहीं मिला। उन्होंने खाद डाली, सिंचाई बढ़ाई और तरह-तरह के उपाय किए, लेकिन समस्या लगातार बढ़ती गई। धीरे-धीरे पूरी फसल कमजोर पड़ने लगी।

जब फसल काटने का समय आया, तो नगर के लोग स्तब्ध रह गए। खेत लगभग खाली थे। जहां सुनहरी बालियां लहलहानी चाहिए थीं, वहां केवल सूखी मिट्टी और बर्बाद पौधे दिखाई दे रहे थे। किसानों के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। पूरे नगर में चिंता फैल गई, क्योंकि इस बार उत्पादन इतना कम हुआ था कि लोगों के पास अगले वर्ष बोने के लिए भी पर्याप्त बीज नहीं बचे थे। जो लोग कुछ समय पहले पक्षियों के खत्म होने पर खुशियां मना रहे थे, वही अब अपने निर्णय पर पछता रहे थे। राजा भी इस विनाश को देखकर चिंतित हो गया। उसने विद्वानों, प्रकृति विशेषज्ञों और अनुभवी किसानों को बुलाकर इस समस्या का कारण जानने का आदेश दिया। कई दिनों तक खेतों का निरीक्षण किया गया। मिट्टी की जांच हुई और पौधों को ध्यान से देखा गया। अंत में एक वृद्ध प्रकृतिविद ने राजा के सामने सच्चाई रखी। उसने बताया कि खेतों की मिट्टी में रहने वाले कीड़ों की संख्या अचानक बहुत बढ़ गई है। यही कीड़े बीजों और पौधों को खा रहे हैं। पहले पक्षी इन कीड़ों को खाकर उनकी संख्या नियंत्रित रखते थे। पक्षियों के कारण खेतों में संतुलन बना रहता था। लेकिन जब सभी पक्षियों को समाप्त कर दिया गया, तो कीड़ों की संख्या तेजी से बढ़ गई और उन्होंने पूरी फसल नष्ट कर दी। यह सुनकर राजा और नगरवासी स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ। जिस पक्षी को वे अपना दुश्मन समझ रहे थे, वही वास्तव में उनके खेतों का रक्षक था। पक्षी केवल दाने नहीं खाते थे, बल्कि वे उन हानिकारक जीवों को भी समाप्त करते थे जो फसल को नुकसान पहुंचाते थे। लोगों को समझ में आया कि प्रकृति का हर जीव किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है। यदि किसी एक जीव को नष्ट किया जाए, तो उसका प्रभाव पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। राजा ने तुरंत नया आदेश जारी किया कि अब नगर में किसी भी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लोगों से कहा गया कि वे पक्षियों के लिए पानी और दाने रखें। आसपास के जंगलों और दूसरे राज्यों से पक्षियों को लाकर नगर में बसाया गया। शुरुआत में पक्षी कम थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब सुबह होते ही पेड़ों पर चहचहाहट गूंजने लगी। खेतों में फिर से जीवन लौट आया। पक्षियों ने कीड़ों को खाना शुरू किया और कुछ वर्षों में मिट्टी का संतुलन फिर से सामान्य हो गया। धीरे-धीरे फसलें दोबारा लहलहाने लगीं। किसानों के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। नगर में समृद्धि वापस आने लगी। लेकिन इस घटना ने सभी को एक गहरी सीख दे दी। लोगों ने समझ लिया कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। मनुष्य अक्सर अपने स्वार्थ में यह भूल जाता है कि इस संसार में हर जीव का अपना महत्व है। कोई भी प्राणी व्यर्थ नहीं है। छोटे से छोटा जीव भी प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अवंतिका नगर की यह घटना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन गई। बुजुर्ग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाकर समझाने लगे कि प्रकृति केवल पेड़-पौधों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विशाल तंत्र है जिसमें सभी जीव एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि किसी एक कड़ी को तोड़ा जाए, तो पूरा तंत्र प्रभावित हो जाता है। पक्षी, पशु, कीड़े, पेड़ और मनुष्य—सभी एक-दूसरे पर निर्भर हैं। यही संतुलन धरती पर जीवन को संभव बनाता है। आज के समय में भी यह सीख उतनी ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक विकास के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं और अनेक जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए प्रकृति का लगातार दोहन कर रहा है। लेकिन वह यह नहीं समझता कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने का परिणाम अंततः मानव जीवन पर ही पड़ता है। जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और प्रदूषण जैसी समस्याएं इसी असंतुलन का परिणाम हैं।

हिंदू अस्मिता की बातें, विवेकानंद सा पहनावा, बंगाल के 'योगी' को CM बनाएगी BJP?

राजनीति में सबसे बड़ा झटका क्या होता है? जब नाम हार जाता है और नैरेटिव टूट जाता है। पश्चिम बंगाल में इस बार यही हुआ है। वो बंगाल जहां ममता बनर्जी सत्ता की परिभाषा थी। जहां ममता से विरोध करना जोखिम भरा था। जहां ममता की इजाजत के बगैर पत्ता तक नहीं हिल रहा था। सत्ता सरकार का ऐसा रुतबा था कि हर गली, हर बूथ, हर फैसले पर कंट्रोल ममता का था। आज उस जमीन पर ममता बनर्जी के साथ खेला है। वो जमीन भगवा मय हो गई है। राम मंदिर, हिंदुत्व और कल्चरल नेशनलिज्म यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इन तीन विषयों को भाजपा ने देश के हर राज्य में धुरी की तरह इस्तेमाल किया है। सफलता भी मिली है। इसी धुरी के इर्द-गिर्द भाजपा बंगाल में भी घूमी जीती भी। लेकिन यह जीत 5 सालों की यात्रा में पहला कदम है और भाजपा तो इस सोच के साथ बंगाल में दाखिल हुई है कि अब टिकना है। तो ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती यह है कि सूबे का मुखिया ऐसे किसी शख्स को बनाया जाए जो इस जीत को पक्का भी कर सके और दोहरा भी सके। कुछ-कुछ वैसा जैसे योगी आदित्यनाथ ने किया या हेमंता विश्वा शर्मा ने। संयासी का भगवा वस्त्र, हिंदू अस्मिता की बातें, मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ सीधी आवाज और राजनीति में कदम रखकर हिंदुओं की रक्षा का वादा। जब हम भारतीय राजनीति में भगवा और सत्ता के मिलन की बातें करते हैं तो सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आता है। कारण सीधा सा है कि एक संयासी और मठ के प्रमुख से लेकर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री तक का सफर तय करके भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की एक नई परिभाषा लिखी। बंगाल में भाजपा बिना चेहरे के चुनाव में उतरी। इस सवाल में उलझी नहीं कि ममता का विकल्प कौन होगा। लेकिन अब उसे अपने 100 से ज्यादा विधायक एक नाम के पीछे इकट्ठा करने हैं। क्या उसके पास कोई ऐसा नेता है? एक नाम आगे किया जा रहा है। उत्पल ब्रह्मचारू पगड़ी से लेकर धोती तक सब कुछ भगवा बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह। बयान भी वैसे ही मुखर। लेकिन सब कुछ योगी जैसा ही नहीं। उत्पल ब्रह्मचारू ने अपने पहनावे में बारीक काम किया है। वह धोती कुर्ता पहनने के बाद शॉलनुमा एक भगवा कपड़ा भी ओढ़ते हैं। जिसे देखकर कहीं ना कहीं आपको विवेकानंद का पहनावा याद आ सकता है। यही कारण है कि इन्हें पश्चिम बंगाल में लोग उत्पल महाराज कहकर बुलाते हैं। फिर जब से इन्होंने भगवा वेशभूषा पर भाजपा का गमछा उड़ा है, तब से यह बंगाल के योगी आदित्यनाथ भी कहे जा रहे हैं। क्या उत्पल को मौका मिल सकता है? आज इसी का एमआरआई स्कैन करेंगे। मगर ध्यान रहे कि उत्पल महाराज की जीत यूं ही नहीं आई। इसके पीछे उत्पल महाराज की वह जड़ है जिसकी गहराई को भाजपा आलाकमान ने बहुत पहले भांप लिया था। दरअसल उत्पल महाराज की पहचान नेता से पहले एक सन्यासी के तौर पर है जो लंबे वक्त तक भारत सेवाश्रम संघ के हिस्सा रहे। उत्पल महाराज साल 2000 में आधिकारिक तौर पर भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े थे। बाद में कालियागंज और कुन्नौर में स्थापित संघ के शाखा के प्रमुख भी रहे।

बंगाल में भारत सेवाश्रम संघ का प्रमुख होने भर से आपके साथ लाखों लोग जुड़ जाते हैं। जिसका कारण इस संघ का दावा और बंगाल में गहरा प्रभाव है। 1917 में इसकी स्थापना स्वामी प्रणवानंद महाराज ने की थी। तब से यह सामाजिक सेवा के काम करता आ रहा है। जैसे इनके बहुत से कार्यकर्ता की भूमिका बाढ़ और कोविड-19 के वक्त में लोगों को राहत पहुंचाने में रही है। इसके अलावा इस संघ का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार है। यह संगठन अस्पताल, स्कूल और आदिवासी कल्याण केंद्र भी चलाता है। 1920 के दशक से ही इस संघ ने बंगाल के ग्रामीण इलाकों खासकर दलितों और पिछड़ी जातियों के बीच जाकर उन्हें हिंदू समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। आज पूरे भारत में इसके आश्रमों और केंद्रों का एक बड़ा नेटवर्क है। यह कुंभ मेला और अमरनाथ यात्रा जैसे बड़े आयोजनों में भी लाखों तीर्थ यात्रियों की सेवा करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बंगाल में इस संघ को मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। जाहिर है संघ से जुड़े संतों की भी अच्छी फॉलोइंग होगी। यही कारण है कि भाजपा ने उत्पल महाराज को चुना और नतीजा जीत में तब्दील हुआ। अब सवाल वही कि जब बंगाल में भाजपा का हिंदुत्ववादी चेहरा काम तो कर गया लेकिन क्या इनके अंदर योगी आदित्यनाथ वाली क्वालिटी है? तो इस सवाल का जवाब उत्पल महाराज के बयानों और भाजपा की रणनीति में मिलता है। उत्पल महाराज का साफ मानना है कि राज्य में तुष्टीरण की राजनीति के कारण हिंदुओं को अपने धार्मिक त्यौहार जैसे रथ यात्रा और रामनवमी मनाने के लिए भी पुलिस से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। एक आध्यात्मिक संगठन में रहकर वे हिंदुओं की इन समस्याओं को पूरी तरह से हल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। जाहिर है उत्पल महाराज हिंदू अस्मिता और हिंदू एकीकरण की बात करते हैं जो सीधे तौर पर भाजपा की विचारधारा से मेल खाती है। उत्पल महाराज ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने संघ के अधिकारियों को चुनाव लड़ने के अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया था, लेकिन जब वे सहमत नहीं हुए, तो उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के एक दिन बाद, 17 मार्च को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। भारत सेवाश्रम संघ पूरी तरह से गैर-राजनीतिक, सामाजिक सेवा और धार्मिक संगठन है। संघ के महासचिव स्वामी विश्वत्मानंद ने पत्र में लिखा किसी भी परिस्थिति में संघ का कोई संन्यासी, ब्रह्मचारी या आश्रम निवासी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के प्रभाव या प्रलोभन में आ जाता है, तो उसका धार्मिक जीवन पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यह उसे त्याग के गौरव से विमुख कर देता है और सांसारिक सुखों की लत में डुबो देता है जबकि हमें संसार के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, सांसारिक ऐश्वर्य की ओर लौटने के लिए अपनी अंतरात्मा और वैराग्य का त्याग करना कभी भी उचित नहीं है।

अभियान

अरब सागर के किनारे विराजमान शिवधाम, जहां आज भी गूंजती है रामायण काल की कथा

भारत को सदियों से आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं की भूमि माना जाता है। यहां के मंदिर केवल पूजा-अर्चना के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय इतिहास, पुराणों और सभ्यता की अमूल्य धरोहर भी हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे अनेक प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, जिनका संबंध त्रेता युग, द्वापर युग या फिर हजारों वर्ष पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ है। इन मंदिरों में केवल धार्मिक महत्व ही नहीं छिपा, बल्कि उनसे जुड़ी कथाएं लोगों को अध्यात्म, भक्ति और संस्कृति के प्रति भी प्रेरित करती हैं। दक्षिण भारत में स्थित एक ऐसा ही अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर है, जिसका संबंध सीधे रामायण काल और रावण की कथा से जोड़ा जाता है। यह मंदिर है कर्नाटक का प्रसिद्ध मुरुदेश्वर मंदिर, जहां भगवान शिव की भव्यता, समुद्र की सुंदरता और पौराणिक इतिहास एक साथ दिखाई देते हैं।

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले की भटकल तहसील में स्थित मुरुदेश्वर मंदिर अरब सागर के किनारे बना हुआ है। यह स्थान तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहां का प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनमोहक दिखाई देता है। दूर-दूर तक फैला नीला समुद्र, लहरों की गूंज और उसके बीच खड़ा विशाल शिव मंदिर श्रद्धालुओं को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति कराता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ समय के लिए सांसारिक चिंताओं को भूलकर भक्ति और शांति के वातावरण में खो जाता है। यही कारण है कि यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पर्यटन और आध्यात्मिक आकर्षण का भी प्रमुख केंद्र बन चुका है। मुरुदेश्वर भगवान शिव का ही एक स्वरूप माना जाता है। प्राचीन समय में इस स्थान को "मृदेश्वर" कहा जाता था, लेकिन बाद में यहां मंदिर के निर्माण और प्रसिद्धि के बाद इसका नाम बदलकर "मुरुदेश्वर" हो गया। इस मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ माना जाता है और इसके पीछे एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि लंका के राजा रावण ने अमरता और अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। रावण भगवान शिव का परम भक्त था और उसने वर्षों तक कठिन साधना कर महादेव को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे आत्मलिंग प्रदान किया। यह आत्मलिंग अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य माना जाता था।

भगवान शिव ने रावण से कहा कि यदि वह इस आत्मलिंग को लंका में स्थापित कर देगा, तो वह अजेय और अमर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी रखी गई थी कि यात्रा के दौरान यदि आत्मलिंग को कहीं जमीन पर रख दिया गया, तो वह वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा और फिर उसे कोई हिला नहीं सकेगा। रावण इस आत्मलिंग को लेकर लंका की ओर रवाना हो गया। देवताओं को जब यह पता चला कि यदि आत्मलिंग लंका पहुंच गया, तो रावण अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा, तब वे चिंतित हो उठे। सभी देवता भगवान गणेश के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी।

कथा के अनुसार भगवान गणेश ने एक बालक का रूप धारण किया और गोकर्ण के पास रावण के सामने प्रकट हुए। उसी समय रावण को संध्या वंदन करने की आवश्यकता महसूस हुई। उसने उस बालक से कुछ देर के लिए आत्मलिंग पकड़ने का अनुरोध किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि यदि वह अधिक देर तक नहीं लौटे, तो वह आत्मलिंग को जमीन पर रख देंगे। रावण पूजा में व्यस्त हो गया और कुछ समय बाद गणेश जी ने आत्मलिंग को धरती पर रख दिया। जब रावण वापस आया, तो उसने आत्मलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे हिला नहीं सका। क्रोध में आकर रावण ने आत्मलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। कहा जाता है कि इसी दौरान आत्मलिंग से जुड़े कुछ भाग अलग-अलग स्थानों पर जा गिरे। जिस वस्त्र में आत्मलिंग लिपटा हुआ था, वह कंदुका पर्वत पर आकर गिरा और वही स्थान बाद में मुरुदेश्वर कहलाया।

शिव पुराण में इस कथा का विस्तृत वर्णन मिलता है और इसी कारण मुरुदेश्वर मंदिर को रामायण काल की घटनाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह मंदिर केवल धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहां स्थित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। समुद्र किनारे स्थापित भगवान शिव की यह प्रतिमा लगभग 123 फीट ऊंची है और इसे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची शिव प्रतिमाओं में गिना जाता है। दूर से देखने पर यह प्रतिमा समुद्र और आकाश के बीच किसी दिव्य दृश्य की तरह प्रतीत होती है।

इस विशाल प्रतिमा को इस प्रकार बनाया गया है कि दिनभर सूर्य की किरणें इस पर पड़ती रहती हैं। प्रतिमा को चांदी जैसे रंग से सजाया गया है, जिससे सूर्य का प्रकाश पड़ते ही यह और अधिक भव्य और चमकदार दिखाई देती है। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण इस प्रतिमा पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव तेजस्वी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हों। समुद्र की लहरों के बीच स्थित यह प्रतिमा श्रद्धा और भव्यता का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है।

मुरुदेश्वर मंदिर की वास्तुकला भी बेहद आकर्षक है। मंदिर का गोपुरम यानी प्रवेश द्वार दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है और इसकी ऊंचाई भी काफी अधिक है। मंदिर के अंदर भगवान शिव का पवित्र शिवलिंग स्थापित है, जिसके दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां आने वाले भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्रावण मास, महाशिवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों पर यहां लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है।

इस विशाल शिव प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार शिवमोग्गा काशीनाथ और उनकी टीम ने किया था। बताया जाता है कि इसे बनाने में लगभग पांच वर्षों का समय लगा और करीब पांच करोड़ रुपये की लागत आई थी। इतनी ऊंची प्रतिमा का निर्माण उस समय एक बड़ी उपलब्धि माना गया था। आज यह प्रतिमा केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय कला और स्थापत्य कौशल का भी उत्कृष्ट उदाहरण बन चुकी है।

मुरुदेश्वर आने वाले पर्यटक केवल मंदिर के दर्शन ही नहीं करते, बल्कि यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लेते हैं। समुद्र किनारे स्थित होने के कारण यहां का वातावरण हमेशा शांत और मनमोहक रहता है। शाम के समय जब सूरज अरब सागर में डूबता है, तब मंदिर और शिव प्रतिमा का दृश्य अत्यंत अद्भुत दिखाई देता है। दूर-दूर से आने वाले लोग इस क्षण को अपने कैमरों में कैद करते हैं। यहां समुद्र तट पर बैठकर ध्यान और साधना करने वाले लोगों की संख्या भी काफी अधिक होती है।

मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहां लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग ऊंचाई से समुद्र और आसपास के क्षेत्र का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। मंदिर के आसपास कई छोटे-बड़े बाजार भी हैं, जहां धार्मिक वस्तुएं, प्रसाद और स्थानीय हस्तशिल्प की चीजें मिलती हैं। इसके अलावा यहां दक्षिण भारतीय भोजन का स्वाद भी पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है।

मुरुदेश्वर मंदिर आज केवल कर्नाटक ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की आध्यात्मिक पहचान बन चुका है। यह स्थान भक्ति, इतिहास, पौराणिक कथाओं और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति भगवान शिव की दिव्यता को महसूस करता है और रामायण काल से जुड़ी उस कथा को याद करता है, जिसने इस स्थान को अमर बना दिया। भारत की सांस्कृतिक विरासत में ऐसे मंदिरों का विशेष महत्व है। वे हमें हमारी प्राचीन परंपराओं, आस्था और धार्मिक इतिहास से जोड़ते हैं। मुरुदेश्वर मंदिर यह संदेश देता है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन आस्था और अध्यात्म की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। समुद्र की लहरों के बीच अडिग खड़ी भगवान शिव की यह प्रतिमा आज भी श्रद्धालुओं को यह विश्वास दिलाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

प्रेम जाल, फर्जी पहचान और सरहद पार की साजिश, बांग्लादेशी युवक ने नाबालिग को बनाया निशाना; प्रयागराज से दबोचा गया आरोपी

झालावाड़। राजस्थान के झालावाड़ जिले में नाबालिग लड़की के कथित अपहरण और उसे प्रेम जाल में फंसाकर बांग्लादेश ले जाने की साजिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज कुछ घंटों के भीतर आरोपी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया। जांच में सामने आया है कि आरोपी मूल रूप से बांग्लादेश का निवासी है, जो टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी फर्जी पहचान के सहारे देश में अवैध रूप से रह रहा था।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के अनुसार, 2 मई 2026 को झालरापाटन थाने में एक परिवार ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों ने आशंका जताई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर किसी युवक ने अपने साथ ले गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। पुलिस ने विशेष टीमों का गठन कर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, संभावित ठिकानों और रिश्तेदारों के यहां तलाशी अभियान शुरू किया।

जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सूचना मिली कि आरोपी नाबालिग को ट्रेन के जरिए कोलकाता लेकर जा रहा है। प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले कि कोलकाता पहुंचने के बाद लड़की को बांग्लादेश ले जाने की योजना बनाई गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन और रेलवे नेटवर्क की मदद से तेजी से कार्रवाई शुरू की। इसके बाद प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी कर 5 मई को आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और नाबालिग लड़की को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने पहले अपना नाम आदित्य उर्फ बादल विश्वास बताया और खुद को झालावाड़ के सलोतिया क्षेत्र का निवासी बताया। लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ में उसकी कहानी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। बाद में उसने स्वीकार किया कि वह मूल रूप से बांग्लादेश का निवासी है और उसने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करवा रखे थे।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी वर्ष 2024 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह अवैध रूप से भारत में रह रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उसने स्थानीय स्तर पर फर्जी पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज बनवाकर अपनी पहचान बदल ली थी, ताकि उसकी वास्तविक नागरिकता सामने न आ सके। आरोपी लगातार अपना निवास स्थान भी बदलता रहा, जिससे उस पर संदेह कम हो सके।

जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी पिछले कुछ समय से नाबालिग लड़की के संपर्क में था। वह फोन के जरिए उससे बातचीत करता था और कई बार

उससे मुलाकात भी कर चुका था। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से नाबालिग को भावनात्मक रूप से अपने प्रभाव में लिया और फिर उसे लेकर फरार हो गया। पुलिस को आशंका है कि लड़की को धीरे-धीरे विश्वास में लेकर उसे सीमा पार ले जाने की योजना पहले से तैयार की गई थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने राज्य और रेलवे नेटवर्क में अलर्ट जारी किया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती, तो आरोपी लड़की को देश से बाहर ले जाने में सफल हो सकता था। पुलिस की तकनीकी जांच और फील्ड इंटेलिजेंस ने इस पूरे ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस पूरे घटनाक्रम ने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी ने भारत में रहते हुए किन लोगों की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और क्या उसके संपर्क किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए थे। पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है, जिन्होंने आरोपी को पहचान छिपाने और स्थानीय दस्तावेज हासिल करने में मदद की। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने वाली टीम को 25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता नाबालिग को सुरक्षित वापस लाना थी, जिसमें सफलता मिली है। साथ ही अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में भी चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फर्जी पहचान के सहारे बाहरी लोगों का लंबे समय तक रहना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। वहीं, नाबालिग बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल संपर्कों के जरिए बहलाने-फुसलाने की घटनाओं को लेकर अभिभावकों में भी चिंता बढ़ गई है। पुलिस अब आरोपी के मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट और यात्रा संबंधी जानकारियों की जांच कर रही है। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी का उद्देश्य केवल लड़की को भगाना था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क और मानव तस्करी जैसी आशंका भी जुड़ी हुई थी। फिलहाल नाबालिग लड़की को सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है और उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है। वहीं आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि डिजिटल संपर्क और फर्जी पहचान के जरिए अपराधी किस तरह किशोरों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों और संपर्कों पर नजर रखें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

बूंदी में ACB की बड़ी कार्रवाई, 25 हजार की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार; पंचायत में फैले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश

बूंदी (राजस्थान)। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कोटा स्पेशल यूनिट ने बूंदी जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। केशोरायपाटन पंचायत समिति की सखावदा ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सतवीर सिंह कुमावत को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे पंचायत प्रशासन में हड़कंप मच गया है और स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के नेटवर्क को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों के भुगतान से जुड़ा हुआ है। परिवादी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत सखावदा गांव में नाली निर्माण, सफाई व्यवस्था सुधार और अन्य बुनियादी विकास कार्य करवाए थे। इन कार्यों के एवज में लगभग डेढ़ लाख रुपये के बिल पंचायत समिति में लंबित थे। आरोप है कि सभी कार्य पूर्ण होने और दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद ग्राम विकास अधिकारी भुगतान जारी करने के लिए लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी केवल पुराने बिलों के

भुगतान के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले कार्यों में किसी प्रकार की अड़चन न डालने और योजनाओं को सुचारू रूप से पास करने के बदले भी अवैध धन की मांग कर रहा था। लगातार दबाव और परेशान किए जाने से तंग आकर पीड़ित ने मामले की शिकायत ACB कोटा कार्यालय में दर्ज कराई।

5 मई 2026 को दर्ज इस शिकायत के बाद ACB ने मामले की गोपनीय जांच शुरू की। प्रारंभिक सत्यापन में रिश्वत मांगे जाने के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पूरी योजना बनाकर ट्रैप ऑपरेशन की तैयारी की गई। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अधिकारी का व्यवहार पहले भी संदिग्ध रहा है और स्थानीय स्तर पर उसकी कार्यशैली को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं, हालांकि किसी ने अब तक औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।

ACB की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। जैसे ही परिवादी ने तय राशि 25 हजार रुपये आरोपी ग्राम विकास अधिकारी को सौंपी, पहले से तैयार टीम ने मौके पर ही उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से पंचायत समिति परिसर में अफरा-तफरी मच गई और वहां मौजूद अन्य कर्मचारी भी हैरान रह गए।

गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की संभावना जताई जा रही है। ACB अधिकारियों के अनुसार अब आरोपी के आवास और अन्य संभावित ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अवैध लेन-देन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा सके।

ACB की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इस कार्रवाई ने एक बार फिर पंचायत स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार की गंभीरता को उजागर किया है। ग्रामीण विकास योजनाओं के नाम पर किस तरह से फाइलों को अटकाकर अवैध वसूली की जाती है, यह मामला उसका ताजा उदाहरण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से होती रहे तो पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है।

फिलहाल आरोपी अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है और संबंधित पंचायत में चल रहे अन्य विकास कार्यों की फाइलों की भी जांच शुरू होने की संभावना है। ACB की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

मुंबई में एफडीए का बड़ा एक्शन, गुटखा माफिया पर शिकंजा; मिलावटी दूध गिरोह का भंडाफोड़, करोड़ों का अवैध माल जब्त

मुंबई। महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा और जनस्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने अप्रैल 2026 में राज्यभर में एक व्यापक और सख्त अभियान चलाते हुए अवैध गुटखा कारोबार और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान ने न केवल अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर प्रशासन की गंभीरता को भी उजागर किया है।

पूरे राज्य में चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 290 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। इन छापों में प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और सुगंधित सुपारी जैसे उत्पादों का बड़ा अवैध भंडार बरामद किया गया। जब्त किए गए माल की कुल कीमत लगभग 2 करोड़ 52 लाख 23 हजार रुपये से अधिक आंकी गई है। यह कार्रवाई राज्य में सक्रिय संगठित गुटखा नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी चोटों में से एक मानी जा रही है।

एफडीए की जांच में सामने आया कि इस अवैध कारोबार में कई संगठित गिरोह शामिल हैं, जो उत्पादन से लेकर वितरण तक एक सुनियोजित नेटवर्क के तहत काम

कर रहे थे। इन गिरोहों के जरिए प्रतिबंधित उत्पादों की अवैध ढुलाई और बिक्री की जा रही थी। प्रशासन ने इस पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए अब तक 288 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं विभिन्न पुलिस थानों में इस मामले से जुड़े 261 एफआईआर दर्ज किए गए हैं।

अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य केवल अवैध माल की जब्ती नहीं था, बल्कि इस पूरे सिंडिकेट को जड़ से खत्म करना भी था। छापेमारी के दौरान कई गोदाम, छोटे निर्माण यूनिट और अवैध पैकिंग सेंटर भी पकड़े गए हैं, जहां बिना अनुमति के इन उत्पादों का निर्माण और री-पैकेजिंग की जा रही थी।

इसी अभियान के दौरान एफडीए और मुंबई क्राइम ब्रांच ने मिलकर वर्सोवा इलाके में एक बड़े दूध मिलावट रैकेट का भी पर्दाफाश किया है। 9 अप्रैल की सुबह की गई संयुक्त कार्रवाई में चार ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां नामी ब्रांडेड दूध के पैकेटों में मिलावट कर उन्हें बाजार में बेचा जा रहा था।

जांच में पाया गया कि आरोपी पहले ब्रांडेड दूध के सीलबंद पैकेटों को खोलते थे और उसमें पानी मिलाकर उसकी गुणवत्ता को कम कर देते थे। इसके बाद उन्हें दोबारा सील कर बाजार में मूल उत्पाद के रूप में बेच दिया जाता था, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ हो रहा था।

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि लगभग 621 लीटर मिलावटी दूध जब्त कर तुरंत नष्ट कर दिया गया। जब्त किए गए दूध की कीमत लगभग 36 हजार रुपये के आसपास बताई गई है। साथ ही जांच के लिए आठ सैंपल प्रयोगशाला भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एफडीए अधिकारियों के अनुसार यह मिलावट सिंडिकेट लंबे समय से सक्रिय था और यह केवल मुंबई तक सीमित नहीं बल्कि आसपास के इलाकों तक फैला हुआ हो सकता है। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और वितरण चैनलों की भी जांच कर रही हैं।

राज्य प्रशासन का कहना है कि ऐसे अवैध कारोबार न केवल सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। विशेष रूप से गुटखा और मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। एफडीए ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर अवैध कारोबार को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में और भी छापेमारी और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है।

कुल मिलाकर, मुंबई और महाराष्ट्र में हुई यह कार्रवाई यह संदेश देती है कि खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब प्रशासन पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है, और ऐसे नेटवर्क को किसी भी कीमत पर चलने नहीं दिया जाएगा।

निजीकरण और महंगी शिक्षा ने गरीबों का शिक्षा पर से भरोसा हिला दिया है : छगनलाल मेवाड़ा

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

भारत में गरीबों के लिए शिक्षा प्राप्त करना कठिन होने का कारण नीतिगत असमानताएं हैं। एक ओर सरकारी संस्थानों का बजट कम कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर निजी शिक्षा की उच्च लागत और कोचिंग केंद्रों की महंगी फीस गरीब परिवारों के लिए वहनीय नहीं है। इसके अलावा, सामाजिक स्थिरता के साधन के रूप में शिक्षा पर उनका विश्वास भी डगमगा रहा है।

आइए नेहरू युग को याद करें। नेहरू के समय में, भारत के गरीब लोग एक सरल क्रांतिकारी विचार में विश्वास रखते थे, शिक्षा को सामाजिक असमानता का एक

बड़ा कारण मानते थे। “पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे” (शिक्षा जाति, गरीबी और जन्मजात वंशानुगत भेदभाव से मुक्ति का एकमात्र रास्ता था)। भारत के संविधान में भी गरीब और वंचित नागरिकों के लिए शिक्षा को एक वादे के रूप में शामिल किया गया था। एक समय था जब सार्वजनिक विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम, सरकारी मेडिकल कॉलेज केवल संस्थान नहीं थे, बल्कि सामाजिक गतिशीलता का आधार थे। लेकिन आज, नीतिगत दृष्टिकोणों के परिणामस्वरूप, भारत के गरीब और वंचित लोगों का शिक्षा पर विश्वास डगमगा रहा है।

दो दशक पहले शिक्षा के निजीकरण का जो दायरा बढ़ा था, उसे भाजपा के 12 वर्षों के शासनकाल में जानबूझकर और तेज कर दिया गया। रणनीति इस तरह बनाई गई कि शिक्षा गरीबों की पहुंच से बाहर हो गई। एक निश्चित वेतन के साथ शिक्षा की अत्यधिक लागत आज लोगों को और गरीब बना रही है। उच्च शिक्षा में निजी पूंजी का प्रवेश 1990 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुआ और 2000 के दशक तक इसने गति पकड़ ली। यह अनुमान लगाया गया था कि निजी पूंजी के प्रवाह से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, लेकिन पिछले तीन दशकों में यह अनुमान पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण साबित हुआ है।

बंगाल में तख्तापलट के बाद हिंसा भड़क उठी, जिससे लोकतंत्र और शांति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ और बंगाल के इतिहास में कभी सत्ता हासिल न कर पाने वाली पार्टी को सत्ता मिल गई। ऐसे में स्वाभाविक ही था कि इस पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता और नेता जीत से उत्साहित थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे इस जीत को पचा नहीं पाए। विजयी भाजपा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उन्मादपूर्ण तरीके से जीत का जश्न मनाने के कारण पूरा बंगाल हिंसा की आग में जल उठा है। इसी वजह से बंगाल हो या कोई और राज्य, सभ्य और सुसंस्कृत समाज भय, चिंता और बेचैनी की लहर से जूझ रहा है।

सबके मन में एक ही सवाल है कि अब बंगाल का क्या होगा? ठीक वैसे ही जैसे मध्य युग में

किसी भी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद आक्रमणकारी सेनाएँ वहाँ तबाही मचा देती थीं और व्यापक विनाश के निशान छोड़ जाती थीं, ठीक उसी तरह विजयी पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता और इस अवसर का लाभ उठाने वाले अपराधी और हिंसक तत्व हिंसा का नग्न नृत्य कर रहे हैं। इस देश में कई चुनाव हुए हैं और होते रहेंगे, इसलिए चुनावों में जीत और हार तो हमेशा होती रहती है। आज एक पार्टी सत्ता में है, कल दूसरी आ सकती है। यही सच्ची लोकतंत्र है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और बंगाल के इतिहास में शुरू हुई हिंसा बंगाल की अनूठी पहचान, संस्कृति और सभ्यता के लिए खतरा बन गई है।

इस प्रकार, अपनी जीत को पचा न पाने वाले उन्मादी भाजपा कार्यकर्ताओं ने दंगा करने वाले तत्वों के साथ मिलकर बंगाल को अराजकता के भंवर में धकेल दिया है। यदि केंद्र सरकार बंगाल में स्थिति को नियंत्रित करने और हिंसा की आग बुझाने के बजाय इस ओर ध्यान नहीं देती है, तो निस्संदेह बंगाल एक और मणिपुर बन जाएगा। और यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है, तो यह लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक होगा।

तमिलनाडु की सियासत में बड़ा टकराव, विजय के शपथ ग्रहण पर राजभवन का ‘ना’; विपक्षी दलों का एकजुट मोर्चा

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय अभूतपूर्व सियासी हलचल देखने को मिल रही है, जहां फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए थलापति विजय की मुख्यमंत्री बनने की राह राजभवन के रुख के कारण फिलहाल थम गई है। तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के प्रमुख विजय ने कांग्रेस सहित कुछ अन्य दलों के समर्थन के साथ सरकार गठन का दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें तत्काल शपथ दिलाने से इनकार कर दिया। राजभवन की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि पहले 118 विधायकों के समर्थन का औपचारिक और प्रमाणित पत्र प्रस्तुत किया जाए, तभी सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसी निर्णय ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार, विजय राज्यपाल से मिलने लोक भवन पहुंचे थे और उन्होंने समर्थन पत्र के आधार पर सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन राज्यपाल ने यह कहते हुए प्रस्ताव को अस्थायी रूप से रोक दिया कि संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार बहुमत का स्पष्ट और औपचारिक प्रमाण आवश्यक है। बताया जा रहा है कि यह दूसरी बार है जब सरकार गठन के प्रस्ताव को राज्यपाल की ओर से स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। इस रुख के बाद राज्य में राजनीतिक तनाव तेजी से बढ़ गया है।

विजय की पार्टी टीवीके ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई थी। हालांकि बहुमत के लिए आवश्यक 118 सीटों के आंकड़े से वह पीछे रह गई।

कांग्रेस के समर्थन के बाद गठबंधन के पास फिलहाल 113 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत से पांच सीटें कम है। यही कारण है कि सरकार गठन की प्रक्रिया अभी भी अनिश्चितता में फंसी हुई है।

राजभवन के इस रुख के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा मोड़ तब आया जब लंबे समय से एक-दूसरे के राजनीतिक विरोधी रहे दल एक साथ खड़े नजर आने लगे। डीएमके, वीसीके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मक्कल निधि मय्यम जैसे दलों ने राज्यपाल के निर्णय का खुलकर विरोध किया है। इन दलों का कहना है कि लोकतंत्र में सरकार गठन की प्रक्रिया विधानसभा के भीतर तय होती है, न कि राजभवन में बहुमत के कागजात की शर्त पर। विपक्षी दलों ने इसे जनादेश और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया है। वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने कहा कि यदि किसी गठबंधन को पर्याप्त समर्थन प्राप्त है, तो उसे सदन के पटल पर बहुमत साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। वहीं डीएमके नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्यपाल का यह रुख राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित प्रतीत होता है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसी स्वर में कहा कि संविधान की भावना यह है कि बहुमत का परीक्षण विधानसभा में होना चाहिए, न कि पहले राजभवन में।

इस पूरे विवाद ने तमिलनाडु की राजनीति को एक असामान्य स्थिति में ला खड़ा किया है, जहां विचारधारात्मक रूप से विपरीत दल भी एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति राज्य में एक बड़े संवैधानिक बहस को जन्म दे सकती है, जिसका प्रभाव आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति पर भी पड़ सकता है।

इस घटनाक्रम ने एक पुरानी राजनीतिक बहस को भी फिर से हवा दे दी है, जिसमें राज्यपाल की भूमिका और उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि कुछ मामलों में राज्यपाल का रुख अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दिखाई देता है, जिससे संवैधानिक प्रक्रिया की एकरूपता पर सवाल उठते हैं।

इस संदर्भ में 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव का उदाहरण भी राजनीतिक हलकों में चर्चा में है, जब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को सरकार गठन का अवसर दिया गया था, जबकि विपक्षी गठबंधन के पास संख्याबल अधिक होने के बावजूद उसे पहले शपथ का अवसर नहीं मिला था। उस समय तत्कालीन राज्यपाल ने बी.एस. येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी और बाद में उन्हें सदन में बहुमत साबित करने के लिए समय दिया गया था। वर्तमान तमिलनाडु प्रकरण में राज्यपाल द्वारा पहले ही बहुमत के प्रमाण की मांग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दोनों मामलों की तुलना से यह बहस और गहरी हो गई है कि क्या राज्यपालों के निर्णय राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं या फिर वे संवैधानिक प्रावधानों की अलग-अलग व्याख्या करते हैं। इस मुद्दे ने अब केवल तमिलनाडु की राजनीति तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है।

फिलहाल राज्यपाल के रुख के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है और राजनीतिक दलों के बीच बातचीत और रणनीति का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस और टीवीके गठबंधन बहुमत जुटाने के लिए नए समीकरणों की तलाश में जुटे हैं, जबकि विपक्षी दल राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ आंदोलनात्मक रुख अपनाने की तैयारी में हैं। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की यह स्थिति आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। सभी की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या टीवीके नेतृत्व बहुमत का आंकड़ा जुटा पाएगा या फिर यह मामला एक लंबे संवैधानिक और राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लेगा।

पश्चिम बंगाल में बड़ा सियासी विस्फोट, विधानसभा भंग; ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में गुरुवार को उस समय भारी उथल-पुथल मच गई जब राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा विधानसभा भंग करने का आदेश जारी किए जाने की जानकारी सामने आई। लोक भवन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया कि यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत राज्यपाल को प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत लिया गया है और इसे 7 मई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है और राजनीतिक दलों के बीच तनाव की स्थिति पैदा कर दी है।

सूत्रों के अनुसार आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करने का कदम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। हालांकि इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ गई है और प्रशासनिक स्तर पर भी असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर न तो राज्य सरकार की ओर से और न ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कोई आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आई है।

इस बीच राजनीतिक हलकों में यह खबर तेजी से फैल रही है कि राज्य की सत्ता संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर इस संबंध में कोई संवैधानिक घोषणा या पुष्टि सामने नहीं आई है। राज्य के प्रशासनिक ढांचे में इस कथित निर्णय के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं और कानूनी विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम की संवैधानिक वैधता पर भी चर्चा कर रहे हैं।

इधर कोलकाता में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की एक अहम बैठक बुलाए जाने की जानकारी सामने आई है। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बैठक में शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे राजनीतिक समीकरण और अधिक जटिल हो सकते हैं। राज्य में इस कथित घटनाक्रम के बीच विपक्षी दलों में भी हलचल बढ़ गई है। विभिन्न दल इस स्थिति पर अपनी रणनीति तय करने में जुटे हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है, हालांकि अब तक किसी प्रकार की आपात स्थिति या संवैधानिक संकट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसी बीच एक अलग राजनीतिक घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के कोलकाता दौरे और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात ने भी राजनीतिक चर्चाओं को नया आयाम दिया है। बताया जा रहा है कि चुनावी नतीजों के बाद यह पहली बड़ी राजनीतिक मुलाकातों में से एक है, जिसमें दोनों नेताओं के बीच वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई।

ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के राजनीतिक संघर्ष और हालिया चुनावी परिस्थितियों पर विचार साझा किए। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के राजनीतिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष जारी रखा है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी एकता को मजबूत करने की आवश्यकता है।

मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी स्वयं अखिलेश यादव का स्वागत करने पहुंचीं और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। इस मुलाकात में राजनीतिक सौहार्द और विपक्षी एकजुटता के संकेत देखने को मिले, जिसे आने वाले समय की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति कई राज्यों में तनाव और अस्थिरता पैदा कर रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दलों को एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आना होगा।

फिलहाल पश्चिम बंगाल में कथित विधानसभा भंग और मुख्यमंत्री पद को लेकर उठे सवालों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आधिकारिक स्तर पर और स्पष्ट जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले 24 से 48 घंटे इस पूरे मामले की दिशा तय करने में बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

7 मई, विश्व एथलेटिक्स दिवस

गुजरात में खेल महाकुंभ की पहल से एथलेटिक्स को मिली नई उड़ान ग्राम से लेकर राज्य स्तर तक खिलाड़ियों की प्रतिभा में आया निखार

▸▸ खेल महाकुंभ 2025 के अंतर्गत नडियाद में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में चमके 9383 खिलाड़ी

▸▸ राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक और हैमर थ्रो सहित 390 इवेंट का आयोजन, विजेता खिलाड़ियों को मेडल और ट्रैकसूट देकर सम्मानित किया गया

गांधीनगर : गुजरात के युवा आज खेल क्षेत्र में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं और खेलों को अपना पेशा बना रहे हैं। इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता को जाता है। 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने खेल महाकुंभ की एक नई पहल की, जिससे राज्य के खिलाड़ियों में नया उत्साह पैदा हुआ है और दूरदराज के क्षेत्रों से भी प्रतिभाएं सामने आ रही हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में फिटनेस, अनुशासन और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2026 के लिए विश्व एथलेटिक्स दिवस की थीम 'स्पोर्ट : बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स' है, जो युवाओं को मजबूत बनाने और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक संबंधों, एकता और समानता को प्रोत्साहन देने में एथलेटिक्स की भूमिका को दर्शाता है। एथलेटिक्स को बेसिक ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है यानी यह सभी खेलों का आधार है।

गुजरात में खेल महाकुंभ पहल के तहत आयोजित होने वाली एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा भी इसी विजन को साकार कर रही है। इस पहल के माध्यम से ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार मंच मिल रहा है।

खेल महाकुंभ 2025 के अंतर्गत राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में 9383 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

इस वर्ष 16 जनवरी से 3 फरवरी के दौरान खेड़ा जिले के नडियाद शहर में खेल महाकुंभ 2025 के अंतर्गत राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा आयोजित हुई, जिसमें राज्य के कुल 9383 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस प्रतिस्पर्धा का हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सुचारू रूप से आयोजन किया।

प्रतिस्पर्धा में अंडर-9, अंडर-11, अंडर-14 और अंडर-17 तथा ओपन एज ग्रुप के 4694 लड़के और 4689 लड़कियां शामिल थीं, जो राज्य में खेल के प्रति बढ़ती रुचि और व्यापक भागीदारी को दिखाता है।

दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक और हैमर थ्रो सहित 390 इवेंट का आयोजन

खेल महाकुंभ 2025 की राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में 30 मीटर से लेकर 5000 मीटर की दौड़, 80, 100, 110 और 400 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल्स), लंबी कूद, ऊंची कूद, बांस कूद, ट्रिपल जंप, गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक, हैमर थ्रो, रिले रेस और तेज चाल जैसी कुल 390 इवेंट्स का आयोजन किया गया। इस प्रतिस्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेडल और ट्रैकसूट प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया।

खेल महाकुंभ की पहल से गुजरात खेल क्षेत्र में अग्रणी बना

खेल महाकुंभ पहल के परिणामस्वरूप गुजरात को सरिता गायकवाड़, मयूर मालविया, रुचित मोरी और मुरली गावित जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिले हैं। डांग की 'गोल्डन गर्ल' सरिता गायकवाड़ ने एशियाई खेल 2018 में महिला 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि मुरली गावित ने 2019 की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतक गुजरात का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। गुजरात सरकार ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देकर राज्य को खेल क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

विक्रमशिला सेतु पर संकट के बाद त्वरित एक्शन, गंगा पार आवागमन के लिए बेली ब्रिज और ट्रस ब्रिज का रास्ता साफ

पटना। बिहार के पूर्वी हिस्से में जीवनरेखा माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु की क्षति के बाद सरकार और तकनीकी एजेंसियों ने युद्धस्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था बहाल करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। भागलपुर को सीमांचल क्षेत्र से जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण पुल के प्रभावित होने से यातायात व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है, जिसे देखते हुए अब अस्थायी और स्थायी दोनों समाधान पर एक साथ काम शुरू किया गया है। गुरुवार को पटना में पथ निर्माण विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने की। इस बैठक में Border Roads Organisation (BRO), IIT Patna की तकनीकी टीम, पुल विशेषज्ञ आलोक भौमिक और कई वरिष्ठ अभियंता शामिल हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा था—क्षतिग्रस्त स्पैन की स्थिति, सुरक्षा मूल्यांकन और यातायात को जल्द से जल्द बहाल करने की रणनीति। बैठक में सबसे पहले विक्रमशिला सेतु की मौजूदा संरचनात्मक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। तकनीकी विशेषज्ञों ने बताया कि क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के लिए त्वरित कदम जरूरी हैं, क्योंकि यह पुल न केवल भागलपुर बल्कि पूरे सीमांचल क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक आवागमन का प्रमुख माध्यम है।

अस्थायी समाधान के तौर पर बेली ब्रिज और ट्रस ब्रिज निर्माण पर सहमति बनी है। अधिकारियों के अनुसार, BRO की सहायता से जल्द ही एक अस्थायी बेली ब्रिज तैयार किया जाएगा, जिससे हल्के और आंशिक यातायात को पुनः शुरू किया जा सकेगा। यह कदम तत्काल राहत प्रदान करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों की आवाजाही में काफी सुधार होगा। इसके साथ ही, एक स्थायी समाधान के रूप में दो लेन वाले ट्रस ब्रिज के निर्माण की भी योजना पर काम शुरू किया गया है। यह ब्रिज आधुनिक डिजाइन और सुरक्षा मानकों के अनुसार बनाया जाएगा और इसमें पैदल यात्रियों के लिए अलग से सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था भी होगी। विभाग ने इस परियोजना को लगभग दो महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है, ताकि लंबे समय तक यातायात बाधित न रहे। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया कि विक्रमशिला सेतु को राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक मानते हुए कार्य में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अभियंताओं और तकनीकी टीमों को लगातार स्थल पर मौजूद रहकर कार्य की निगरानी करनी होगी।

चांदखेड़ा रोड–साबरमती 'D' केबिन नई ब्रॉड गेज Y-कनेक्टिविटी लाइन का CRS निरीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न

पश्चिम सर्किल के रेल संरक्षा आयुक्त (CRS) ई. श्रीनिवास ने आज दिनांक 07 मई 2026 को पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में चांदखेड़ा रोड–साबरमती 'डी' केबिन (लगभग 1.00 किमी) इंटरसेक्शन की नई ब्रॉड गेज Y-कनेक्टिविटी लाइन का संरक्षा निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इस नई लाइन पर मोटर ट्रॉली द्वारा विस्तृत निरीक्षण किया तथा लाइन की संरक्षा एवं परिचालन क्षमता का आकलन किया। इसके अतिरिक्त इस सेक्शन पर स्पीड ट्रायल भी सफलतापूर्वक किया गया।

इस निरीक्षण के दौरान प्रदीप गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), श्री वेद प्रकाश, मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद सहित निर्माण एवं ओपन लाइन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

साबरमती 'डी' केबिन बाईपास का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उत्तर एवं पूर्वी भारत से आने-जाने वाली ट्रेनों, विशेषकर सौराष्ट्र क्षेत्र की ट्रेनों, को व्यस्त साबरमती 'डी' केबिन क्षेत्र में प्रवेश किए बिना वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। इससे ट्रेनों की आवाजाही अधिक तेज एवं निर्बाध होगी तथा सौराष्ट्र क्षेत्र से आने-जाने वाले यात्रियों के यात्रा समय में भी कमी आएगी। इसके अलावा लोको रिवर्सल समाप्त होने से साबरमती लाइन पर अधिक ट्रेनें चलाने के लिए अधिक सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

चांदखेड़ा रोड बाईपास के माध्यम से ट्रैफिक डायवर्ट होने से अहमदाबाद (कालूपुर) एवं साबरमती स्टेशनों पर ट्रेनों का दबाव कम होगा, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी। यह नई Y-कनेक्टिविटी भविष्य में अधिक ट्रेनों के संचालन में भी सहायक सिद्ध होगी।

इस परियोजना के पूर्ण होने के साथ उत्तर गुजरात एवं सौराष्ट्र क्षेत्र के यात्रियों को आधुनिक एवं बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बेहतर रेल संपर्क के कारण चांदखेड़ा एवं आसपास के क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों तथा रियल एस्टेट विकास को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे अहमदाबाद की आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी।

नई लाइन भारतीय रेलवे को एक वैकल्पिक एवं सुगम परिचालन मार्ग प्रदान करेगी, जिससे पश्चिम रेलवे नेटवर्क में यात्री सुविधाओं एवं रेल संचालन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

भारतीय शिपिंग सेक्टर को बड़ा बूस्ट, जहाजों पर सब्सिडी योजना 2030-31 तक बढ़ाई गई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के समुद्री परिवहन और शिपिंग उद्योग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर लागू सब्सिडी योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। अब यह योजना वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी, जिससे भारतीय शिपिंग कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में अतिरिक्त मदद मिलेगी।

पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी जानकारी के अनुसार इस फैसले का उद्देश्य भारत में पंजीकृत जहाजों को बढ़ावा देना और देश के समुद्री बेड़े (merchant fleet) को अधिक मजबूत बनाना है। सरकार का मानना है कि इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में भागीदारी भी बढ़ेगी और घरेलू शिपिंग उद्योग को दीर्घकालिक स्थिरता मिलेगी।

यह योजना पहली बार जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई थी, जिसे 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत लागू किया गया था। उस समय वित्तीय प्रावधान के रूप में 1,624 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय शिपिंग कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय निविदाओं (global tenders) में प्रतिस्पर्धी बनाना था।

योजना के तहत उन भारतीय कंपनियों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिनके जहाज भारत में पंजीकृत हैं और जो सरकारी आयात माल ढुलाई या अंतरराष्ट्रीय शिपिंग अनुबंधों में भाग लेते हैं। नियमों के अनुसार, 1 फरवरी 2021 के बाद भारत में पंजीकृत और 10 वर्ष से कम पुराने जहाजों को विदेशी कंपनियों की सबसे कम बोली (L1) की तुलना में अधिकतम 15 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा सकती है। हालांकि यह सहायता केवल बोली के अंतर के बराबर सीमित रहती है।

इसके अलावा, 1 फरवरी 2021 से पहले पंजीकृत और 10 वर्ष से कम पुराने जहाजों को अधिकतम 10 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। यह प्रावधान विशेष रूप से उन भारतीय शिपिंग कंपनियों को राहत देता है, जिनके पास पहले से परिचालन में मौजूद आधुनिक जहाज हैं।

सरकार ने इस योजना में यह भी स्पष्ट किया है कि 20 वर्ष से अधिक पुराने जहाज इस सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे। इसका उद्देश्य समुद्री बेड़े को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।

मंत्रालय के अनुसार योजना के विस्तार के साथ भारत के शिपिंग सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता मजबूत होगी। साथ ही, देश के भीतर जहाज निर्माण और समुद्री रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार में एक मजबूत खिलाड़ी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वर्तमान में वैश्विक शिपिंग बाजार में प्रतिस्पर्धा काफी तेज है, और ऐसे में सरकारी समर्थन भारतीय कंपनियों को लागत और प्रतिस्पर्धा दोनों स्तरों पर राहत प्रदान करेगा। सरकार का यह भी मानना है कि इस नीति से विदेशी शिपिंग कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और भारत धीरे-धीरे अपनी समुद्री आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सकेगा। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स और निर्यात-आयात प्रणाली भी अधिक सुदृढ़ होगी। कुल मिलाकर, इस निर्णय को भारत के समुद्री और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालिक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था और व्यापारिक क्षमता पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।

अपग्रेडेड यात्री आरक्षण प्रणाली (Passenger Reservation System) में अगस्त से रेल गाड़ियों की होगी शिफ्टिंग

40 साल पुरानी इस प्रणाली से अपग्रेडेड सिस्टम पर गाड़ियों की शिफ्टिंग होते समय यात्रियों को परेशानी न हो इसलिए रेल मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

आज रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में 40 साल पुरानी आरक्षण प्रणाली में अपग्रेडेड सिस्टम पर गाड़ियों की शिफ्टिंग होते समय यात्रियों को परेशानी न हो इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिए । इस बैठक में रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू भी उपस्थित थे।

1986 में शुरू हुई इस प्रणाली में पिछले 40 साल में कई छोटे बदलाव किए गए । लेकिन अब इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया है । अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर इसके क्षमता का विस्तार किया गया है ।

रेल आरक्षण प्रणाली ने कई महत्वपूर्ण पड़ाव देखें है I वर्ष 2002 में भारतीय रेलवे ने ticketing में internet का प्रयोग शुरू किया। आज ये प्रणाली इतनी लोकप्रिय है कि देश की ज्यादातर आबादी खिड़की की ओर रुख नहीं करती। देश में आज जितनी भी ticketing की माँग है उसका बड़ा हिस्सा (₹88%) online माध्यम से होता है।

भारतीय रेल का मोबाइल ऐप रेलवन यात्रियों के बीच बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। रेलवन ऐप की शुरुआत पिछले साल जुलाई में हुई थी। एक साल से कम समय में ही देशभर में अब तक 3.5 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं।

इस ऐप के लोकप्रिय होने के कई कारणों में से सबसे बड़ा कारण यह है कि यह ऐप देश के आम आदमी को रेल संबंधी सभी जानकारियाँ तो देता ही है, टिकटिंग तथा अन्य सेवाओं से जुड़ी उनकी शिकायतों का भी निपटारा करता है।

आज जब आप अपनी टिकट बनाते हैं, तो रेलवन ऐप आपको यह बताता है कि आपकी वेटिंग में दिख रही टिकट कन्फर्म होगी या नहीं। टिकट के कन्फर्म होने की सटीक संभावना भी अब आपको एआई के माध्यम से रेलवन ऐप बताने लगा है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। रेलवन ऐप पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53 प्रतिशत से बढ़कर अब 94 प्रतिशत तक पहुँच गई है। रेलवन ऐप में इस तरह की कई एकीकृत एवं आधुनिक सुविधाएँ हैं, जो रेल संबंधी अन्य सभी सेवाओं को भी अपने में समाहित किए हुए हैं। जैसे - आरक्षित, अनारक्षित तथा प्लेटफॉर्म आदि विभिन्न प्रकार के टिकटों की बुकिंग, रद्दीकरण तथा रिफंड। इस के साथ साथ आपके हमारे मौजूदा टिकट की वेटिंग status की ताजा स्थिति, ट्रेन के आने जाने का समय, ट्रेन की मौजूदा स्थिति, ट्रेन के आने-जाने का platform, आप के coach की position, रेल मदद जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रेलवन (RailOne) app पे हैं। अपनी यात्रा के दौरान आप अपना food भी रेलवन (RailOne) app पर order कर सकते हैं। App आपको ये विकल्प देता है कि आप की seat तक आपका मनपसंद खाना पहुंच सके। आरामदायक व सेवापरक सुविधाओं से लैस यह रेलवन (RailOne) app तेजी से लोकप्रिय हो रहा है ।

इसके साथ-साथ आपके मौजूदा टिकट की वेटिंग स्थिति की ताज़ा जानकारी, ट्रेन के आने-जाने का समय, ट्रेन की वर्तमान स्थिति, ट्रेन के आने-जाने का प्लेटफॉर्म, आपके कोच की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी रेलवन ऐप पर उपलब्ध हैं। अपनी यात्रा के दौरान आप रेलवन ऐप पर भोजन भी ऑर्डर कर सकते हैं। यह ऐप आपको यह सुविधा देता है कि आपकी सीट तक आपका मनपसंद खाना पहुँच सके। आरामदायक एवं सेवापरक सुविधाओं से लैस यह रेलवन ऐप तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

रोज़ाना इस app के माध्यम से देश भर में 9.29 लाख टिकिटे book हो रही हैं। इसमें 7.2 लाख टिकटें अनारक्षित तथा अन्य 2.09 लाख आरक्षित टिकटें हैं। अनारक्षित टिकटों में platform टिकट भी शामिल है। Android तथा IOS पर रेलवन (RailOne) app को लोग काफी पसंद कर रहे है। जहाँ 3 करोड़ 16 लाख लोगो ने इसे गूगल प्लेस्टोर से अब तक डाउनलोड किया है, वहीं 33.17 लाख लोगो ने इसे ऐपल phones में डाउनलोड किया है।

देश में यात्रियों के लिए भारतीय रेल एक जीवन रेखा है - भारतीय रेल ने 2024-25 में यात्रियों के टिकटों पर 60,239 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। यह रेलवे पर यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 43% की छूट के बराबर है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपये है, तो टिकट की कीमत केवल 57 रुपये है।

एपल का भारत में बड़ा ग्रीन इन्वेस्टमेंट, 150 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना पर 100 करोड़ रुपये का निवेश

नई दिल्ली। अमेरिकी टेक दिग्गज एपल ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक निवेश करते हुए लगभग 100 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा की है। कंपनी का यह कदम उसके वैश्विक कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। भारत में यह निवेश न केवल ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव का संकेत देता है, बल्कि देश की ग्रीन इकॉनमी को भी नई गति देने वाला माना जा रहा है।

इस निवेश के तहत एपल भारत की प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी CleanMax के साथ साझेदारी में लगभग 150 मेगावाट से अधिक क्षमता की नई स्वच्छ ऊर्जा इकाइयों का विकास करेगी। यह परियोजना देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थापित की जाएगी, जिससे सौर और अन्य नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

कंपनी के अनुसार इस परियोजना से उत्पन्न ऊर्जा हर साल लगभग 1.5 लाख भारतीय घरों की बिजली जरूरतों को पूरा करने के बराबर होगी। इस पहल से न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता भी कम होगी।

एपल ने स्पष्ट किया है कि इस निवेश का मुख्य उद्देश्य भारत में उसके सप्लाई चेन नेटवर्क को पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित बनाना है। कंपनी पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि वह वर्ष 2030 तक अपने पूरे वैश्विक संचालन को 100 प्रतिशत कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहती है, और भारत में यह परियोजना उसी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।

CleanMax के साथ साझेदारी एपल के लिए नई नहीं है। इससे पहले भी दोनों कंपनियां मिलकर भारत में कई रूफटॉप सोलर परियोजनाओं पर काम कर चुकी हैं, जिनका उद्देश्य एपल के ऑफिस और रिटेल स्टोर्स को पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करना रहा है।

एपल की पर्यावरण और सप्लाई चेन नवाचार उपाध्यक्ष सारा चैंडलर ने इस पहल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कंपनी के लिए पर्यावरण संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि नवाचार की दिशा में एक प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता और इसके प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रयासों में योगदान देना एपल के लिए गर्व की बात है।

इस निवेश को केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे भारत में हरित उद्योग और स्थायी विकास मॉडल को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के वैश्विक निवेश भारत को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा एपल ने भारत में पर्यावरण संरक्षण और सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए भी नई साझेदारियों की घोषणा की है। कंपनी ने WWF-India के साथ मिलकर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने, रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू किया है। साथ ही एपल ने Acumen के साथ साझेदारी करते हुए भारत में ग्रीन स्टार्टअप्स और सामाजिक उद्यमों को समर्थन देने की भी योजना बनाई है। इसके तहत अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्योजी कृषि और सर्कुलर इकॉनमी से जुड़े उद्यमों को अनुदान और मेंटरशिप सहायता प्रदान की जाएगी। कुल मिलाकर, एपल का यह निवेश भारत के ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में देखा जा रहा है। यह न केवल देश में स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार को गति देगा, बल्कि वैश्विक कंपनियों के लिए भारत को एक आकर्षक हरित निवेश गंतव्य के रूप में भी स्थापित करेगा।